dicted because it is a natural calamity. It is also not possible for the State Government alone to check sea erosion because a huge amount will have to be spent. So, I request the Central Government to have an independent and separate scheme and allocation of more funds for checking sea erosion. More allocation of funds be made in the coming budget. Konkan railwayline which comes from Bombay and connects Manglore and coastal region of Karnataka be completed as early as possible to strengthen tourism in Karnataka.

1.00 P.M.

With these few words I conclude.

Agitation by Doctors/Medical teachers in Rajasthan

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इस विशेष उल्लेख के द्वारा लोक हित का अत्यावश्यक मुद्दा भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान में लम्बे समय से क्लीनिकल शिक्षक चिकित्सा अधिकारियों एवं नोन-क्लीनीकल शिक्षक चिकित्सा अधिकारियों की हड़ताल के कारण सम्पूर्ण राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं मे बाधा उत्पन्न हो चुकी है और जनता बड़ी परेशान है । समस्या का कारण यह बना है कि चौथे वेतन आयोग के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत लेक्चरर्स एवं प्रोफेसर्स का वेतनमान तो काफी अच्छा बढ़ गया और और उस बढ़े हुए वेतनमान को राज्य सरकारों ने भी स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके वेतन के भुगतान में 80 प्रतिशत की भागीदारी युनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन की होती है एवं 20 प्रतिशत ही राशि राज्य सरकारों द्वारा दी जानी होती है । परन्तु इसके विपरीत स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत शिक्षक चिकित्सा अधिकारी का वेतनमान शिक्षा जगत में कार्यरत लेक्चरर्स एवं प्रोफेसर्स के मुकाबले में नहीं बढ़ा है । यह वास्तव में विडम्बना का विषय है कि शिक्षा जगत मे कार्यरत लेकचरर्स एवं प्रोफेसर्स जो केवल ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर पद ग्रहण कर लेते हैं उसके विपरीत डाक्टर्स बनने के लिए उनको शिक्षा के क्षेत्र में लम्बा संघर्ष करना पड़ता है और उसके उपरान्त ही चिकित्सा अधिकारी लेक्चरर्स एवं प्रोफेसर्स हो पाते हैं । इस प्रकार चिकित्सा जगत में कार्यरत लेक्चरर्स एवं प्रोफेसर्स भी शिक्षा जगत में आर्टस, कोमर्स साईन्स इत्यादि में कार्यरत लेक्चरर्स एवं प्रोफेसर्स के ही समानन्तर वेतन पाने के अधिकारी हैं बल्कि उनको (डाक्टर्स) अधिक वेतन मिलना चाहिये । चूंकि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति गम्भीर होने से उनके द्वारा चिकित्सा अधिकारियों का वेतनमान बढ़ाना एक समस्या है इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस मामले में किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप कर समानान्तर पद वाले व्यक्तियों को समानान्तर वेतन मिलने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है । केन्द्रीय सरकार के लिए भी सभी राज्यों की व्यवस्था करने का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है । परन्तु राजस्थान के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की गई हड़ताल को दृष्टिगत रखते हुए एवं राजस्थान में पिछले चार पांच वर्षों से लगातार अकाल की गम्भीर समस्या होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है और इस कारण राज्य सरकार का मानस डाक्टरों के वेतनमान को बढ़ाने का होने के उपरान्त भी वह बढ़ा नहीं पा रही है । उपरोक्त चिकित्सा अधिकारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में गत वर्ष भी नोटिस दिया था परन्तु शताब्दी का भीषणतम अकाल होने के कारण उन्होंने उस समय अपना हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया था और राज्य सरकार ने उनके मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन भेजा था एवं युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन द्वारा चिकित्सा अधिकारियों को भी अधिक वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में लिखा था । यह सब होने पर भी अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने के फलस्वरूप इस वर्ष यह समस्या पुनः उत्पन्न हो गई है और डाक्टर्स हड़ताल पर चले गये है जिसको लगभग तीन सप्ताह हो चुके है । अस्पतालों में मरीजों की हालत बहुत गम्भीर है एवं चिकित्सा सुविधाओं की समय पर उपलब्धी नहीं होने के कारण काफी मरीज दम

[श्री भंवर लाल पवांर]

तोड़ चुके हैं। अतः आपके माध्यम से भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से पुरजोर शब्दों से निवेदन है कि अविलम्ब इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार किसी न किसी रूप में विशेषस हायता प्रदान करे, इस समस्या का समाधान कराया जा सके और राजस्थान की गरीब जनता को राहत मिल सके।

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आप को इस स्पेशल मेंशन से सम्बद्ध करता हूं और मांग करता हूं कि इस समस्या का शीघ्र निराकरण कराया जाए क्योंकि राजस्थान की जनता इस हड़ताल के कारण अत्यधिक परेशन है।

Disturbance in TV reception due to shifting of TV Tower to Pitampura

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से दिल्ली दूरदर्शन के टावर बदले जाने से टेलिविजिन के दर्शकों को जो असुविधा हुई है उसके सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

महोदय, 2 दिसम्बर, 1988 को मैंने माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी से अतारांकित प्रश्न संख्या 2806 के द्वारा जाना चाहा था कि :

— क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली हाल ही में अपने टी.वी. टावर का स्थान बदलकर पीतमपुरा, दिल्ली ले गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 21 नवम्बर, 1988 के "वीर अर्जुन" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार ने टी० वी० टावर का स्थान बदल कर अपनी अदूरदर्शिता दिखाई है जिससे संसद मार्ग के आस पास रहने वाले लाखों लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

किस प्रकार से सूचना और प्रसारण मंत्रालय असत्य उत्तर देता है इसकी जानकारी मिलती है कि (ख) में मैंने पूछा था कि "वीर अर्जुन" में जो समाचार छपा है उस पर मंत्रालय का ध्यान दिलाया गया है या नहीं। जो उत्तर मिला है, मैं उसी पर विशेष ध्यान माननीय उपसभाध्यक्ष जी आपका आकर्षित करना चाहूंगा। उत्तर है कि "दिनांक 12-11-88 के "वीर अर्जुन" के न तो प्रातःकालीन संस्करण में और न ही सायंकालीन संस्करण में कोई ऐसी समाचार मद थी। तथापि यह सही है कि...."तो यह उत्तर बिलकुल गलत है। "वीर अर्जुन" अखबार 21 नवम्बर के प्रातःकालीन संस्करण का मैं उल्लेख कर रहा हूं, उसकी प्रति भी आपकी सेवा में भेज दूंगा। यह कितनी चिंता की बात है कि "वीर अर्जुन" अखबार में छपता है और मंत्रालय उत्तर देता है कि छपा ही नहीं, न सवेरे के संस्करण में और न शाम के संस्करण में। इसको मैं उद्धृत कर रहा हूं।

"टी०वी० टावर बदलकर अदूरदर्शिता का परिचय दिया। नई दिल्ली, 20 नवम्बर (म)। राजधानी नागरिक कल्याण समिति ने दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के संसद मार्ग कार्यक्रम प्रसारण टावर से अकस्मात प्रसारण बंद कर रोहिणी टावर से आरम्भ करने के निर्णय को अदूरदर्शिता बताते हुए कहा है कि आनन-फानन में नवनिर्मित टावर से प्रसारण करके दूरदर्शन कार्यक्रमों को दूर-दराज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के दावे एकदम खोखले हैं।

समिति के महासचिव श्री प्रीतम धारीवाल ने बताया कि सच्चाई तो यह है